Industry to the speech of the Minister of State for Textiles is available. However, there is general appreciation about the need to get prepared for a totally competitive environment. Government has initiated a number of steps to facilitate modernisation of the textiles and clothing industry and thus enable it to prepare itself for facing the challenges of free trade in textiles and clothing.

गुजरात में जनता कपड़े का वितरण

4541. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में गरीब वर्गों से संबंधित लोगों को जनता कपड़ा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों को जनता कपड़े का वितरण किये जाने के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान गुजरात राज्य को की गई जनता कपड़े की आपूर्ति उसकी वास्तविक मांग की तुलना में अपर्याप्त थी;

(घ) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को जनता कपड़े की वास्तव में की गई आपूर्ति के जिले-वार ब्यौरे सहित गुजरात राज्य द्वारा की गई मांग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात में ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों के जरूरतमंद व्यक्तियों को जनता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हाँ ।

(ख) जनता कपड़ा तैयार करने वाले प्रत्येक राज्य को समस्त उत्पादन को अपने ही राज्य में उपयोग करने की अनुमती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) गुजरात में उत्पादित जनता कपड़ा गुजरात राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, उचित दर दुकानों और गुजरात राज्य हथकरघा अधिकरणों के खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित लक्षित उपभोक्ताओं को बेचा जाता है ।

वस्त्र उद्योग के समक्ष पेश आ रही समस्याएं

4542. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वस्त्र उद्योग को बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं का निवारण करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) इस समय वस्त्र उद्योग में कोई भारी कमियां नहीं हैं । तथापि, आधुनिकीकरण आदि के लिए निधियों की आवश्यकता को उपर्युक्त स्तर पर प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है ।

Quota Premium on Export of Readymade Garments

4543. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a quota premium in the export of ready-made garments and certain persons have been taking advantage of this at the cost of small and genuine exporters because of the delay in the release of quotas ;

(b) whether it is a fact that representations have been presented to Government not to withhold quotas and to release them in good time; if so, what action has been taken on them ; and

(c) what steps have been taken to facilitate the release of quota-limits under categories 334/634, 335/635 for 1994 on FCFS basis and what are the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) The Garment Export Entitlements (Quota) are allocated under the provisions of the Garment Export Entitlement Distribution Policy (Quota Policy). The policy does not stipulate payment of a quota premium in the export of readymade garments. However, the export entitlements under the Past Performance Entitlement System and the Non-Quota Exporter's Entitlement System are transferable. Since the availability of export entitlements in certain countries/categories is less- than the demand, it is possible that the export entitlements in such country/categories are being transferred at a premium.